साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार 31 अक्टूबर-06 नवंबर , 2022, वर्ष-8, अंक-30

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा

मध्यप्रदेश हरित सूचकांक की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य

प्रदेश में जंगल-पार्कों के आधार पर तय होगा सिटी ग्रीन इंडेक्स

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ को साकार करने मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवर्धन पूजा की। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय गोवर्धन पूजा समारोह में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अब सिटी ग्रीन इंडेक्स तैयार कराएगी। इसके आधार पर शहरों को रैंकिंग दी जाएगी। इसके मापदंड तय किए गए हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि शहर की हवा दूषित तो नहीं है। शहरों में जंगल की क्या स्थिति है और सिटी पार्क सिकुड़ तो नहीं रहे हैं। सबसे अधिक जोर हरित परिवहन (ई-वाहनों के उपयोग) पर रहेगा। प्रयोग के तौर पर 16 नगरीय निकायों से इसकी शुरुआत की जा रही है। बाद में इसे प्रदेश के अन्य शहरों में लागू किया जाएगा।

धरोहर को सुरक्षित रखने का संकल्प- सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कहा हमारी जीडीपी ग्रॉस एंवायरनमेंट प्रोडक्ट के बिना अधूरी है। प्रदेश सरकार ने इसी तारतम्य में ग्रीन इनिशियेटिव शुरू किया है। उन्होंने पेड़ लगाने, बिजली बचाने, पानी बचाने, लकड़ी की जगह गौ-काष्ठ का इस्तेमाल करने, प्राकृतिक खेती करने, गौग्रास के लिए कुछ न कुछ देने, फसलों की पराली न जलाने और सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने का संकल्प जनता को दिलाया।

गांव से शहर तक पेड़ लगाने के लिए आरक्षित होगी सरकारी जमीन

गोबर से सीएनसी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होगा

सीएम ने कहा कि मप्र में 1.87 करोड़ से ज्यादा गौवंश है। मैं सम्पूर्ण समाज से अपील करता हूं कि हम गोवंश बचाने के लिए प्रयास करें। मप्र में अभी 1,700 गौशालाएं हैं, 1,404 पूरी हो गई हैं। 1,800 गौशाला हम बना रहे हैं। गोवर्धन योजना के तहत गैस और सीएनजी के निर्माण के लिए इंदौर में प्रयास चालू हो गया है। अगर ढंग से गौशाला चलाएं तो गौशाला आत्मनिर्भर बन जाएंगी। जबलपुर जिले में 21 करोड़ की लागत से गो मूत्र और गोबर से सीएनसी बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होगा।

गोवर्धन पूजा मात्र एक कर्मकांड नहीं है। यह प्रकृति की पूजा है। यह धरती को बचाने का एक महा अभियान है। वह हमें शुद्ध पर्यावरण देता है, वह हमारी गायों को घास देता है। उसके पेड़ों से कई तरह के फल हमें मिलते हैं, तो जो हमें कुछ देता है। वह हमारे लिए देवता है। हमको उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। क्योंकि आज ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है।
शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

शहरों को रैंकिंग दी जाएगी

स्वच्छता में शिखर छूने की कोशिश में जुटी राज्य सरकार अब सिटी ग्रीन इंडेक्स तैयार कराएगी। इसके आधार पर शहरों को रैंकिंग दी जाएगी। इसके मापदंड तय किए गए हैं। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि शहर की हवा दूषित तो नहीं है। शहरों में जंगल की क्या स्थिति है और सिटी पार्क सिकुड़ तो नहीं रहे हैं। सबसे अधिक जोर हरित परिवहन (ई-वाहनों के उपयोग) पर रहेगा।

16 निगम में ग्रीन सिटी इंडेक्ट रैंकिंग की शुरुआत

सीएम ने 16 नगर निगम में ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर शहर को ग्रीन रखने के लिए प्रयास करना होगा। ग्रीन सिटी इंडेक्स में सिटी पार्क प्रबंधन के अलावा, शहर में वन क्षेत्र बढ़ाने का काम, वायु गुणवत्ता बेहतर करने, नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की सुविधा पर नंबर दिए जाएंगे। ग्रीन वाहनों की संख्या को बढ़ाना है। इलेक्ट्रानिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाएंगे। यह ग्रीन सिटी इंडेक्स की रैंकिंग के लिए हम करेंगे।

नगर पालिकाओं में भी करेंगे लागू

सीएम ने कहा कि अभी हम 16 शहरों में ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग लागू कर रहे है, लेकिन अगले चरण के लिए मैं यह निर्देश दे रहा हूं कि नगर पालिकाओं में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी कि कौन सा शहर ग्रीन है और उसको पुरस्कृत करने का काम भी करेंगे। स्वच्छता के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वान किया और मप्र की जनता उठ कर खड़ी हुई। मुझे यह कहते गर्व है कि देश में मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर एक है।

ज्यादा दिन बरसात के कारण इस बार खाद की बढ़ी डिमांड

प्रदेश में डीएपी और यूरिया खाद की कमी से जूझ रहे किसान

भोपाल। जागत गांव हमार

दिवाली के बाद प्रदेश में रबी सीजन की बोवनी शुरू हो गई है। चना, मसूर, सरसों के साथ गेहूं की बोवनी के लिए डीएपी और यूरिया खाद के लिए किसानों को सोसायटी के चक्कर काटना पड़ रहा है। गुना जिले में 10 हजार टन डीएपी खाद की कमी है, जबकि विदिशा में अब तक 2917 टन यूरिया वितरित कराया जा चुका है। 2188 टन का स्टाक होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक किसानों तक नहीं पहुंचा है। इसी तरह डीएपी खाद की 7847 टन उपलब्धता का दावा किया जा रहा है, जबकि 4667 टन वितरित किया गया है। इस बार खाद की ज्यादा डिमांड होने की वजह बरसात ज्यादा दिन तक हुई है। बोवनी के लिए जमीन में बतर नहीं आई, जिससे चना, मसूर, सरसों के साथ गेहूं की बोवनी एक साथ शुरू हो गई है। वहीं, हर साल चना और मसूर की बोवनी पहले हो जाती है, जबकि गेहूं की बोवनी बाद में होती है।

जरूरत से कम मिला खाद

अशोकनगर जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी चारों खाद मिलाकर 70 हजार मीट्रिक टन खाद की और जरूरत है जिसमें से 37,200 मीट्रिक टन ही मिला है। रायसेन जिले के बेगमगंज में गोदाम पर खाद लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सागर जिले में मार्कफेड के गोदाम में यूरिया खत्म हो गया है। डीएपी का दो दिन का ही स्टॉक बचा है। सागर में जिले में रबी सीजन की बोवनी के लिए 21 हजार टन यूरिया और 12500 मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है। यहां पिछले दो दिनों में 1900 मैट्रिक टन खाद ही आई है। मार्कफेड की नई गल्ला मंडी और मकरोनिया स्थित गोदामों में यूरिया नहीं बचा है।

डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला बने राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि के कुलपति

भोपाल। मप्र के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने डॉ. अरविंद कुमार शुक्ला को ग्वालियर स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि का कुलपति नियुक्त किया। डॉ. शुक्ला वर्तमान में भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल में परियोजना समन्वयक के पद पर तैनात हैं। डॉ. शुक्ला का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष का होगा। शुक्ला को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई पुरष्कार मिल चुके हैं। वर्ष 2016 के लिए राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी की फैलोशिप, भारतीय परिषद द्वारा चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट एआईसीआरपी पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पादप पोषण संस्थान, नॉर्क्रॉस द्वारा वर्ष 2016 के लिए आईपीएनआई-एफएआई पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। वर्ष 2014 के लिए इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन, बेल्जियम द्वारा आईजेडए-एफएआई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2004 और 2015 के लिए धीरू मोरारजी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे।

-तिलहनी फसलों की खेती का रकबा भी बढ़ाया जा रहा

कमर्शियल फार्मिंग के लिए जीएम सरसों को मिली मंजूरी

भोपाल। जागत गांव हमार

खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए तिलहनी फसलों की खेती का रकबा भी बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में अब जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दे दी है, जो किसानों के लिये एक अच्छी खबर है। जीएम सरसों यानी आनुवांशिक रूप से संसोधित सरसों की खेती से तेल का उत्पादन बढ़ाने में खास मदद मिलेगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है, क्योंकि भारत अभी भी अपनी जरूरत का 65 फीसदी खाद्य तेल आयात करते है, जिसमें 1 लाख करोड़ खर्च होता है। फिलहाल। जीएम सरसों की हाइब्रिड किस्म धारा मस्टर्ड हाइब्रिड -11 को जीईएसी से ही मंजूरी है। इसकी खेती के लिए भारत सरकार ने मंजूरी नहीं है, जिसके चलते इस रबी सीजन में ये किस्म खेती-किसानी से उपलब्ध नहीं होगी।

20 साल का इंतजार खत्म

जीएम सरसों की धारा मस्टर्ड हाइब्रिड -11 को 20 साल बाद मंजूरी मिली है। ये कृषि क्षेत्र से जुड़ी खाद्य आवश्यकताओं के लिए पहली मंजूरी है। इसका पेटेंट दिल्ली विवि के पूर्व वाइस चांसलर डॉ. दीपक पेंटल द्वारा विकसित किया गया है, जिसे मंजूरी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रेजल कमेटी की 147वीं बैठक में प्रस्तावित किया गया था। 18 अक्टूबर को हुई इस बैठक में जीईएसी ने जीएम सरसों को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी केंद्र ने इसकी खेती के लिए अनुमति नहीं दी है, इसलिए इस रबी सीजन में खेती करना मुश्किल होगा।

धारा मस्टर्ड हाइब्रिड -11 की खूबियां

जीएम सरसों की धारा मस्टर्ड हाइब्रिड -11 में दो एलियन जीन है। इन जीन्स को बैसिलस एमाइलोलिकेफेशियन्स नामक मिट्टी के जीवाणु से अलग करते हैं। इससे सरसों की कमर्शियल फार्मिंग करके अच्छी क्वालिटी और अधिक उत्पादन लेने में मदद मिलेगी।

कृषि विशेषज्ञों की सलाह: इस समय करें सब्जियों की खेती

तापमान को ध्यान में रख करें सरसों की बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

इस समय ज्यादातर किसान धान की कटाई कर चुके हैं, जबकि रबी की फसलों की तैयारी भी किसान कर रहे हैं, ऐसे में किसान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, हर हफ्ते पूसा समाचार और कृषि सलाह के जरिए उनकी समस्याओं का समाधान करता है। किसानों को सलाह है कि खरीफ फसलों (धान) के बचे हुए अवशेषों (पराली) को ना जलाएं। क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणे फसलों तक कम पहुचती है, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रकिया प्रभावित होती है जिससे भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह है कि धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) को जमीन में मिला दें इससे मृदा की उर्वकता बढ़ती है। साथ ही यह पलवार का भी काम करती है। जिससे मृदा से नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पूसा डीकंपोजर कैप्सूल का उपयोग चार कैप्सूल/हेक्टेयर किया जा सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की फसल यदि कटाई योग्य हो गयी तो कटाई शुरू करें। फसल कटाई के बाद फसल को 2-3 दिन खेत में सुखाकर गहाई कर लें। उसके बाद दानों को अच्छी प्रकार से धूप में सूखा लें।

किसान सरसों की बोवनी में देरी न करें

भंडारण के पूर्व दानों में नमी 12 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बोवनी के लिए खाली खेतों को तैयार करें और उन्नत बीज व खाद की व्यवस्था करें। उन्नत प्रजातियां- सिंचित परिस्थिति- (एचडी 3226), (एचडी 2967), (एचडी 3086), (एचडी 2851)। बीज की मात्रा 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर। नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किग्रा प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान सरसों की बोवनी में ओर अधिक देरी न करें। मिट्टी जांच के बाद यदि गंधक की कमी हो तो 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई पर डालें।

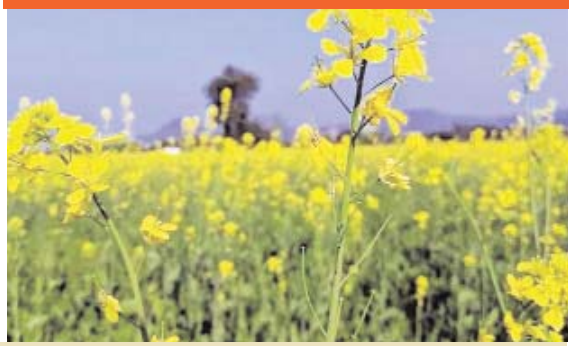

मृदा में उचित नमी का ध्यान रखें

बोवनी से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में- पूसा विजय, पूसा सरसों-29, पूसा सरसों-30, पूसा सरसों-31। बीज दर- 5-2.0 किग्रा प्रति एकड़। बोवनी से पहले खेत में नमी के स्तर को अवश्य ज्ञात कर ले ताकि अंकुरण प्रभावित न हो। बोवनी से पहले बीजों को कैप्टान 2.5 ग्रा. प्रति किग्रा बीज की दर से उपचार करें। बोवनी कतारों में करना अधिक लाभकारी रहता है। कम फैलने वाली किस्मों की बोवनी 30 सेंमी और अधिक फैलने वाली किस्मों की बोवनी 45-50 सेंमी दूरी पर बनी पंक्तियों में करें। विरलीकरण द्वारा पौधे से पौधे की दूरी 12-15 सेंमी कर ले। तापमान को ध्यान में रखते हुए मटर की बोवनी में ओर अधिक देरी न करें अन्यथा फसल की उपज में कमी होगी तथा कीड़ों का प्रकोप अधिक हो सकता है।

लहसुन की बोवनी का सही समय

बोवनी से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। बीजों को कवकनाशी कैप्टान या थायरम 2.0 ग्रा. प्रति किग्रा बीज की दर से मिलाकर उपचार करें उसके बाद फसल विशेष राईजोबियम का टीका अवश्य लगाएं। गुड़ को पानी में उबालकर ठंडा कर ले और राईजोबियम को बीज के साथ मिलाकर उपचारित करके सूखने के लिए किसी छायेदार स्थान में रख दें और अगले दिन बोवनी करें। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बोवनी कर सकते है। बोवनी से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में-जी-1, जी-41, जी-50, जी-282. खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें।

इस सप्ताह कर सकते हैं चने की बोवनी

तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुवाई इस सप्ताह कर सकते है। बोवनी से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60-80 किग्रा तथा बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 80-100 किग्रा प्रति है। बीज की आवश्यकता होती है। बोवनी 30-35 सेंमी दूर कतारों में करनी चाहिए। प्रमुख काबुली किस्में- पूसा 267, पूसा 1003, पूसा चमत्कार (बीजी 1053), देशी किस्में-सी. 235, पूसा 246, पीबीजी 1, पूसा 372। बोवनी से पूर्व बीजों को राइजोबियम और पीएसबी के टीकों (कल्चर) से अवश्य उपचार करें। इस मौसम में किसान गाजर की बोवनी मेड़ों पर कर सकते है। बोवनी से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। उन्नत किस्में- पूसा रूधिरा। बीज दर 4.0 किग्रा प्रति एकड़।

बोवनी से पहले उपचारित करें बीज

बोवनी से पूर्व बीज को केप्टान-2 ग्रा. प्रति किग्रा बीज की दर से उपचारित करें। खेत में देसी खाद, पोटाश और फांस्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। गाजर की बुवाई मशीन द्वारा करने से बीज 1.0 किग्रा प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है जिससे बीज की बचत तथा उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इस मौसम में किसान इस समय सरसों साग- पूसा साग-1, मूली- जापानी व्हाईट, हिल क्रीन, पूसा मृदुला (फ्रेंच मूली); पालक- आल ग्रीन,पूसा भारती, शलगम- पूसा स्वेती या स्थानीय लाल किस्म; बथुआ- पूसा बथुआ-1, मेथी-पूसा कसुरी, गांठ गोभी-व्हाईट वियना, पर्पल वियना तथा धनिया- पंत हरितमा या संकर किस्मों की बुवाई मेड़ों (उथली क्यारियों) पर करें।

पौधशाला भूमि से उठी क्यारियों पर बनाएं

बोवनी से पूर्व मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। इस मौसम में ब्रोकली, फूलगोभी तथा बंदगोभी की पौधशाला तैयार करने के लिए उपयुक्त है। पौधशाला भूमि से उठी हुई क्यारियों पर ही बनाएं। जिन किसानों की पौधशाला तैयार है वह मौसम को ध्यान में रखते हुए पौध की रोपाई ऊंची मेड़ों पर करें। मिर्च और टमाटर के खेतों में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। किसान गुलाब के पौधों की कटाई-छटाई करें। कटाई के बाद बाविस्टीन का लेप लगाएं ताकि कवकों का आक्रमण न हो। इस मौसम में गैदें की तैयार पौध की मेड़ों पर रोपाई करें। किसान ग्लेडिओलस की बोवनी भी इस समय कर सकते हैं।

सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री ने देखा निर्माण कार्य

सागर में दिसंबर तक पूरा होगा डेयरी विस्थापन का प्रोजेक्ट

सागर। जागत गांव हमार

सागर में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रतौना स्थित डेयरी विस्थापन प्रोजेक्ट स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रतौना में डेयरी व्यवसाय के लिए प्लाट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जल्द निगम परिषद की बैठक बुलाकर तय की जाए। इस दौरान मंत्री सिंह को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि 15 दिसंबर तक डेयरी विस्थापन के लिए आवश्यक संरचनात्मक कार्य पूरे कर प्लाट आवंटन के लिए स्थल उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वास्तविक कीमत पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर डेरी विस्थापन स्थल रतौना में भूखंड उपलब्ध कराए जाएं। साथ ही 30 दिसंबर तक सभी आवश्यक कार्य पूर्ण किए जाएं।

रतौना ग्राम डेयरी विस्थापन

सागर के रतौना ग्राम में 18 हेक्टेयर में 8 करोड रुपए से अधिक की राशि से डेयरी विस्थापन स्थल तैयार किया जा रहा है। मंत्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान डेयरी विस्थापन के सभी कार्य दिसंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिसमें प्रमुख रूप से रोड, पानी, बिजली, सीवर लाइन समेत अन्य व्यवस्थाएं कराई जाएं। डेयरी मालिकों को शीघ्र नोटिस दिए जाएं। जिसमें पहले आओ पहले पाओ ऑफर के साथ वास्तविक कीमत पर प्लाट उपलब्ध कराए जाएं। डेयरी स्थल पर किसी भी प्रकार का लाभांश ना लेते हुए वास्तविक कीमत पर ही प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।

डेयरी एक जनवरी से शुरू होनी चाहिए

मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी डेयरी 1 जनवरी से यहां शुरू हो जानी चाहिए। जिससे कि सागर स्वच्छ सुरक्षित हो सके। परियोजना के प्रतिनिधि अनुराग सोनी ने बताया कि 18 हेक्टेयर में 392 डेयरी मालिक अपनी डेयरी स्थापित करेंगे। यहां 1000, 2000, 6000 स्क्वायर फुट के प्लाट उपलब्ध हैं। सभी भूखंड पशुओं की संख्या की आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए जाएंगे। निरीक्षण के दौरान मंत्री सिंह के साथ सांसद राजबहादुर सिंह, विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर प्रतिनिधि सुशील तिवारी, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, कलेक्टर दीपक आर्य, नगरनिगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला आदि मौजूद थे।

-रवि सीजन में 15 दिन लेट हुई फसल की बोवनी

अशोकनगर में सिर्फ 20 प्रतिशत हो सकी बोवनी, सरसों का बढ़ा रकबा

अशोकनगर। जागत गांव हमार

अशोकनगर में इस बार आवश्यकता से अधिक हुई बारिश के कारण रवि सीजन की फसल की बोवनी लेट होने लगी है। इस बार लगभग बोवनी 15 दिन लेट चालू हुई है। वैसे तो रबी सीजन की फसलों की बोवनी अक्टूबर-नवंबर माह में होती है, लेकिन ज्यादातर किसान अक्टूबर के आखिरी समय तक पूरी फसलों की बोवनी कर देते थे। हालांकि अब तक लगभग 20 प्रतिशत ही किसानों ने फसलों की बोवनी की है। जिसमें सबसे अधिक सरसों की बनी हुई है। अक्टूबर माह तक ज्यादातर सभी फसलों की बोवनी हो जाती है। केवल धनियां की फसल पीछे होती है। लेकिन इस बार अक्टूबर माह से समय में केवल 20 प्रतिशत ही फसल की बोवनी हो पाई है। अभी तक जो फसलों की बोवनी है, उनमें सबसे अधिक सरसों की फसल की बोवनी की गई है। जिले में सामान्य औसतन वर्षा 882 मिलीमीटर है। लेकिन यहां 50 मिलीमीटर अधिक बारिश हुई थी। जिसकी वजह से अक्टूबर माह के आखिरी समय में भी जमीन में नमी बनी हुई है। जिसकी वजह से किसानों की फसल की समय पर बोवनी नहीं हो पा रही। इस बार प्रदेश से 14 अक्टूबर को मानसून की विदाई हुई है। लगभग 15 दिन पहले बारिश का दौर थमा है। इस वजह से खरीफ सीजन की पकी हुई फसल काफी समय तक खडी रही। फिर फसल की कटाई शुरू हुई। जिसके बाद ही बोवनी शुरू हो पाई है। काफी समय किसानों को खेत तैयार करने में लग गया। जिसके बाद इक्का-दुक्का फसल की बोवनी शुरू हुई। पांच दिन पहले ही फसल की बुवाई शुरू हुई है। जबकि अभी भी कई स्थान ऐसे हैं। जहां पर खेतों में नमी होने की वजह से जुताई नहीं हो पाई है।

फसल में भारी नुकसान सर्वे कराने की गुहार

इधर, अशोकनगर जिले के सेहराई में इस बार फिर किसानों को खरीफ सीजन की फसल में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले तीन-चार साल से सोयाबीन की फसल में नुकसान होने के कारण क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसानों ने सोयाबीन की जगह धान की बोवनी की थी। इस दौरान कई किसानों ने पानी की कमी के चलते सीधी बोने वाली धान की फसल लगाई थी। सीधी बोने वाली धान की फसल में अधिक मात्रा में खरपतवार हो गई। इससे धान की फसल बर्बाद हो गई। अब किसान धान की फसल की कटाई कर रहे हैं। इसमें किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है। क्षेत्र के किसान अशोक सेन, गिरधारी कुर्मी, जंडेल सिंह, शिवलाल साहू ने बताया कि इस बार उन्होंने अपने खेत में सीधी बिजाई की तकनीक से धान की फसल लगाई थी। सीधी धान की बोवनी के बाद उन्होंने पर्याप्त मात्रा में खरपतवार नाशक दवाओं का छिड़काव भी किया लेकिन दवा के छिड़काव के बाद भी खरपत वार नियंत्रित नहीं हो सका। इससे उनकी धान की फसल की लागत भी नहीं निकल रही है। किसानों ने बताया कि उनकी पहले ही उड़द और सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है। अब बीच हुई धान की फसल की नष्ट हो गई है। आगामी फसल की तैयारी के लिए खेतों की सफाई कराने में फिर उन्हें भारी लागत लगाना पड़ रहा है। बार-बार फसल खराब होने से किसान कर्जे में डूब रहा है। प्रशासन ने उनकी फसल का अभी तक सर्वे भी नहीं कराया है। किसानों ने प्रशासन से जल्द ही उनकी फसल का सर्वे कराने की मांग की है।

2022-23 के में 4.6 गुना ज्यादा देशी आलू का निर्यात

देशी आलू की खेती किसानों को दे सकती है डबल मुनाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

आलू की खेती से किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है। अगर आप भी आलू की खेती से कम समय में डबल मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए आलू की अच्छी किस्मों के अलावा आप अपने खेत में देशी आलू की खेती करें। आलू की देशी किस्म की देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे अधिक मांग है। लेकिन जिन देशों में देशी आलू की खेती कम पैमाने पर होती है, उन्हें भारत का आलू निर्यात होता है। सरकारी आकड़ों के मुताबिक, भारत ने साल 2022-23 के समय लगभग 4.6 गुना ज्यादा देशी आलू का निर्यात किया था। ऐसे में यह देश के किसानों के लिए मुनाफे की खेती साबित हो सकती है।

सूर्या किस्म 75 दिनों में तैयार

देशी आलू की खेती 60 से 90 दिनों के अंदर अच्छे से तैयार हो जाती है। किसानों को आलू की अगेती खेती के बाद गेहूं की पछेती खेती भी एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को सूर्या किस्म से बोवनी करनी चाहिए।

प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल उत्पादन

खेत में इस किस्म की बोवनी से फसल 75 से 90 दिनों के अंदर तैयार हो जाती है और साथ ही किसानों को प्रति हेक्टेयर फसल से लगभग 300 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त होता है। अगर आप कम समय में आलू का उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अपने खेत में कुफरी अशोक, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर किस्मों की बोवनी कर सकते हैं।

इन बातों का ध्यान रखें

- आलू की खेती से पहले किसानों को खेत की भूमि को समतल कर लेना चाहिए और फिर अच्छे से जल निकासी की व्यवस्था करें।
- देशी आलू के कंदों का अच्छे से चुनाव करें। क्योंकि इसके बीजों की मात्रा इस किस्म के कंदों पर निर्भर करती है।
- प्रति एकड़ खेत से आप करीब 12 क्विंटल कंदों की बुवाई का काम सरलता से कर सकते हैं।
- देशी आलू की बुवाई के लिए यह समय उपयुक्त है। देखा जाए तो 15 से 20 अक्टूबर का समय अच्छा होता है।
- बोवनी करने से पहले कटे हुए कंदों का उपचार सही तरीके से करें। ताकि फसल में किसी भी तरह के रोग-कीट न लग सके।
- कीट-रोग से बचाने के लिए कंदों को 0.25 प्रतिशत इंडोफिल एम 45 के घोल में 5-10 मिनट तक अच्छे से डुबोकर रखें और फिर इसे सुखा दें।
- कंदों का सही से उपचार करने के बाद किसानों को इसे 14-16 घंटों तक अच्छे छायादार स्थान पर छोड़ दें।

गेहूं का नैनो बीज कम खाद में देगा अच्छा उत्पादन

मध्यप्रदेश के 35 जिलों में नैनो गेहूं की किसान करेंगे बोवनी

भोपाल। जागत गांव हमार

आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटेड कंपनी एलसीबी फर्टिलाइजर ने गेहूं का नैनो कोटेड पार्टिकल सीड तैयार किया है। इसे बोने के बाद 35 दिनों तक पानी की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही भीषण गर्मी में भी फसल खराब नहीं होगी। एलसीबी कंपनी ने अभी गेहूं के बीज पर प्रयोग किया है, जो सफल रहा है। इस साल प्रदेश के 35 जिलों में इस बीज की बोवनी की जाएगी।

गेहूं के बीज में नैनो पार्टिकल और सुपर एब्जार्वेंट पॉलिमर की कोटिंग की गई है। कंपनी के इंक्यूबेटेर अक्षय श्रीवास्तव ने बताया कि गेहूं पर जिस पॉलिमर की कोटिंग की गई है, वह 268 गुना अधिक पानी सोख लेता है और 35 दिनों तक इसे सोखे रहता है। इसके बाद धीरे-धीरे पानी छोड़ता है। इसके अलावा जीवित जीवाणुओं का संयोजन भी दिया जाता है। इसकी मदद से यह खाद को बनाएगा और बार-बार खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाद में जैविक नैनो पार्टिकल का प्रयोग किया गया है, जो वैक्टीरिया को 78 डिग्री के तापमान में भी जिंदा रखता है।

पैदावार में 15 फीसदी की बढ़त

इस बीज के प्रयोग से पैदावार में 15 फीसदी की बढ़त, सिंचाई 33 फीसदी कम और लागत में 48 फीसदी की कटौती होती है। अक्षय ने कहा कि सामान्य गेहूं की फसल 120-150 दिनों में तैयार होती है। इसमें तीन से चार सिंचाई की जरूरत होती है। इसमें मात्र दो सिंचाई में भी काम हो सकता है। यूपी के 35 जिलों के अलावा बिहार, झारखंड में भी इस पर काम किया जा रहा है। अक्षय ने कहा कि इस तकनीक से एक कैप्सूल भी तैयार किया जो आपके पौधों को 35 दिनों तक पानी देता रहेगा। पानी के साथ पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे।

मुंबई में आयोजित होगा विश्व मसाला सम्मेलन

भोपाल। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस विश्व मसाला उद्योग सबसे बड़ा समूह है। यह पिछले तीन दशकों से मसाला कृषकों और व्यापारियों को क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार-विमर्श करने का मंच देता है। इस वर्ष सम्मेलन देश में है, इसलिए ये कार्यक्रम उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय मसाला बोर्ड अभी से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुट गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (डब्ल्यूबीसी) में जी-20 देशों के व्यापार मंत्री, उद्योग संघ, नियामक अधिकारी और आयात-निर्यात से जुड़े प्रमुख देशों के मसाला व्यवसायी शामिल होंगे। 14वें संस्करण में केवल विश्व में पैदा होने वाली मसालों की उन्नत किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कांग्रेस एक स्पाइस एक्सपो का आयोजन भी करेगी। प्रदर्शनी में भारतीय मसाला उद्योग की प्रोडक्शन चेन, हेल्थ सेक्टर, एक्सपेरीमेंट और नवाचारों के साथ मॉर्डन स्पाइस इंडस्ट्री मॉडल को प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन में 50 देशों की मसाला उत्पादों की प्रदर्शनियां और इन देशों के 1000 प्रतिनिधियों के प्रतिभाग करने की संभावना है। सम्मेलन का आयोजन 16-18 फरवरी के बीच सीडको कन्वेंशन सेंटर, नवी मुंबई में होगा। कार्यक्रम के लिए वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ने इस वर्ष की थीम 'विजन 2030 स्पाइस' रखी है।

मोबाईल एप के माध्यम से फसल की होगी बिक्री

किसान आनलाइन मंडी में बेच सकते हैं अपनी उपज

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड द्वारा किसानों को कृषि उपज विपणन के क्षेत्र में अभिनव कदम उठाते हुए मोबाईल एप के माध्यम से अपनी कृषि उपज का विक्रय अपने घर, खलिहान, गोदाम से कराने की सुविधा प्रदान की गई है।

मंडी बोर्ड ने बताया कि सर्वप्रथम अपने एंड्राइड मोबाईल पर प्ले स्टोर में जाकर मंडी बोर्ड भोपाल का मोबाईल एप एमपी फॉर्म गेट डाउनलोड करना होगा तथा एप इंस्टाल कर विक्रय पंजीयन पूर्ण करना होगा।

एप में दर्ज करना होगा जानकारी

फसल विक्रय के समय किसानों को अपनी कृषि उपज के संबंध में मंडी फसल, ग्रेड-किस्म, मात्रा एवं वांछित भाव की जानकारी दर्ज करना होगा। किसानों द्वारा अंकित की गई समस्त जानकारियां चयनित मंडी के पंजीकृत व्यापारियों को प्राप्त जाएगी तथा प्रदर्शित होगी। व्यापारी द्वारा फसल की जानकारी एवं बाजार की स्थिति के अनुसार अपनी दरें ऑनलाईन दर्ज की जाएगीं जिसका किसान को एप में मैसेज प्राप्त होगा। जिसके उपरांत आपसी सहमति के आधार पर चयनित स्थल पर कृषि उपज का तौल कार्य होगा। कृषि उपज का तौल कार्य होने के बाद ऑनलाईन सौदा पत्रक एवं भुगतान पत्रक जारी किया जाएगा और शासन, मंडी बोर्ड के नियमानुसार नगर या बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार किसान मोबाईल एप के माध्यम से मंडी में आए बिना अपने घर, गोदाम, खलिहान से भी अपनी कृषि उपज का विक्रय कर सकते हैं।

दैनिक भाव की जानकारी भी मिलेगी

प्रदेश के किसान अब इस एप किसान प्रदेश की मंडियों में विक्रय की जाने वाली उपजों के दैनिक भाव की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों से इस एप को अपने एंड्राइड मोबाईल में इंस्टाल कर राज्य शासन एवं मंडी बोर्ड की इस अभिनव पहल का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है।

गांव में भी मिलेंगे सांची के उत्पाद

भोपाल। मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा सांची उत्पादों को प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा जिले के पालखंदा और नरवर ग्राम में सांची उत्पाद के विक्रय केन्द्र शुरू किए गए। इससे ग्रामीणों को सांची उत्पादों की सुविधा के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ डॉ. सीबी सिंह ने बताया कि सांची ग्रामीण विक्रय केन्द्रों की स्थापना सतत रूप से जारी रहेगी। कोशिश की जाएगी कि दुग्ध संघ से संबंधित सभी दुग्ध सहकारी समितियों को ग्रामीण सांची विक्रय केन्द्र पार्लर के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी।

किसान अच्छे उत्पादन के लिए करें पूसा 28 सरसों की खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

देश में रबी सीजन की फसलों की बुवाई का समय शुरू हो चुका है। ऐसे में किसान अपने खेत में रबी सीजन की ऐसी फसलों को लगाना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें डबल मुनाफा प्राप्त हो सके। ऐसे में सरसों की खेती लाभकारी साबित हो सकती है। रबी सीजन में सरसों को प्रमुख नकदी फसल कहा जाता है। भारत में सरसों को फसल से तेल निकालने के लिए अधिक उगाया जाता है। बाजार में भी सरसों की सबसे अधिक मांग होती है। इसलिए किसान सरसों की उन्नत किस्म की बोवनी कर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों के लाभ के लिए कई नई-नई किस्मों के बीजों को तैयार किया गया है। इन्हीं नई किस्मों

में से एक सरसों की उन्नत किस्म पूसा सरसों-28 है, जो किसानों को कम समय में अच्छा उत्पादन देती है।

बोवनी के 105 दिनों अच्छे से पक जाती है- सरसों की इस किस्म से किसानों को फसल का अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। यह किस्म बुवाई के 105 से 110 दिनों के अंदर ही अच्छे से पक जाती है। देखा जाए तो पूसा 28 किस्म के बीजों से उत्पादन 1750 से 1990 किलो तक होता है। इस किस्म से केवल तेल ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए हरे चारे भी तैयार किए जाते है। इसके अलावा इनके बीजों में 21 प्रतिशत तक तेल की मात्रा पाई जाती है। पूसा सरसों 28 हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन राज्यों की मिट्टी व जलवायु इसकी खेती के लिए उपयुक्त है।

इन बातों का रखें ध्यान

रबी सीजन में सरसों की खेती के लिए 5 अक्टूबर से 31अक्टूबर तक का समय उपयुक्त माना जाता है। सरसों की खेती से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को खेत में छिड़काव विधि या फिर कतार विधि का उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से फसल पर निगरानी रखना आसान हो जाता है और साथ ही निराई-गुड़ाई करना भी सरल हो जाता है। किसान चाहे तो इसके लिए देसी हल या सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैविक विधि के इस्तेमाल से किसानों को इस किस्म से डबल मुनाफा प्राप्त होगा। इसके अलावा किसानों को बीजों के बेहतर अंकुरण के लिए 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी का भी ध्यान रखना चाहिए।

जीएम सरसों से तिलहन में आत्मनिर्भरता की दरकार

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिण्ड) म.प्र.

देश में तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अब जीएम सरसों की खेती होगी। भारत की जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑपरेशन कमेटी (जीईएसी) ने जेनेटिकली मॉडिफायड (जीएम) सरसों की नई किस्म डीएमएच 11 को क्षेत्र परीक्षण के लिए जारी कर दिया गया है। पिछले अनुभवों के आधार पर देखा जाये तो भारत में अब तक जीएम फसल के रूप में सिर्फ बीटी कॉटन को ही अनुमति दी गई है। जबकि पर्यावरणविदों एवं कृषि जानकारों के विरोध के कारण देश में बीटी बैंगन के क्षेत्र परीक्षण के उपरांत भी इसको उगाने की अनुमति नहीं मिल पाई थी। जीएम फसलें कितनी उपयोगी होगीं यह आने वाले कुछ वर्षों के बाद ही तय होगा।

बताया जा रहा है कि सरसों की इस जीएम प्रजाति को वर्ष 2002 में तैयार किया गया था। इसके बाद से पूरी दुनियां और भारत में इसके प्लॉट स्तरीय प्रदर्शन कराये जा रहे थे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वैज्ञानिकों की देखरेख में कराये गये प्रदर्शनों के बाद दावा किया गया है कि जीएम सरसों की डीएमएच 11 किस्म भारत की कई स्थानीय सरसों की प्रजातियों के मुकाबले 30 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखती है।

अब जीएम सरसों की क्षेत्र परीक्षण के लिए जारी की गई प्रजाति के तहत: व्यावसायिक रिलीज से पहले किसानों के खेतों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लेना होगा। भारत देश में सरसों की इस प्रजाति को पहली ट्रांसजेनिक खाद्य फसल के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर भारत सहित सम्पूर्ण भारत में सरसों की फसल को प्रमुख तिलहन फसल के रूप में उगाया जाता है। देश में उत्पादन और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाये तो सरसों, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख तिलहन फसलें हैं। देश में सोयाबीन के बाद सरसों का उत्पादन दूसरे नंबर पर आता है। सरसों उत्तर भारत के राजस्थान, मप्र, उप्र, हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों की प्रमुख तिलहनी फसल है।

सरसों की फसल में कम पानी तथा कम लागत की आवश्यकता होती है। जानकारों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से सरसों के उत्पादन में ठहराव सा आता जा रहा है। हांलाकि देश में कई प्राइवेट कंपनियों द्वारा किसानों को सरसों की हाइब्रिड प्रजातियों के बीज की भी बिक्री की जा रही है। बताया जा रहा कि सरसों की हाइब्रिड प्रजातियों से अच्छा उत्पादन मिलने के साथ ही फसल में रोग और बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त हुई है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केन्द्र, भरतपुर के वैज्ञानिकों द्वारा भी बेहतर सरसों की प्रजातियों के विकास में निरंतर अतुलनीय योगदान दिया जा रहा है। बावजूद इसके देश में खाद्य तेल की बढ़ती मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। भारत सरकार पाम तेल के लिए पाम की खेती को भी मिशन मोड में आगे करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है।

भारत में सरसों की हाइब्रिड किस्मों का चलन अभी काफी कम हैं। देश के अधिकतर किसान अभी सरसों की शंकुल प्रजातियों की खेती पर ही भरोसा करते हैं। हांलाकि सरसों की हाइब्रिड प्रजातियों की तुलना में इन किस्मों का बीज काफी सस्ता और विश्वसनीय है। भारत के इतर सरसों की हाइब्रिड प्रजातियों को कई देशों में प्रमुखता से अपनाया जा रहा है। जिसमें कनाडा में 85 प्रतिशत, यूरोप में 90 प्रतिशत और चीन में 70 प्रतिशत तक राई से विकसित की गई हाइब्रिड सरसों की खेती की जा रही है।

ऐसे में भारत में जीएम सरसों के आगाज होने के बाद प्रमुख यक्ष प्रश्न यह है कि क्या इससे से देश में तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल हो सकेगी। सरसों का तेल एक खाद्य तेल है, क्या जीएम सरसों की किस्म से प्राप्त तेल खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से मानव सहित पालतू पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बेहतर और सुरक्षित होगा। यह एक चिंताजनक पक्ष हो सकता है जिसके बारे में आने वाले कुछ वर्षों के बाद ही पता चल सकेगा।

सुरक्षा और असर के बारे में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस के वरिष्ठ वैज्ञानिक के. विजय राघवन का कहना है कि बार्नेस और बारस्टार आधारित हाइब्रिड राई का इस्तेमाल कनाडा में 1996, अमेरिका में 2002 और ऑस्ट्रेलिया में 2007 से हो रहा है। अकेले कनाडा में 2013 में 70 लाख टन राई और इसका बना 23 लाख टन तेल का निर्यात किया गया है। लेकिन किसी पर दुष्प्रभाव की बात 1996 से अब तक सामने नहीं आई है। वहीं भारत में भी डीएमएच 11 से मनुष्यों में एलर्जी, जहर पहुंचने या पर्यावरण को नुकसान के आंकलन के लिए विस्तृत परीक्षण किए गए हैं। यदि सब कुछ अच्छा रहता है और जीएम सरसों की इस किस्म को उगाने के लिए जारी कर दिया जाता है तो भारत सरकार को खाद्य तेल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। भारत ने 2021-22 में खाद्य तेल के आयात पर 1899 करोड़ डॉलर खर्च किये हैं। जीएम सरसों उगाकर उत्पादन में बढ़ोत्तरी करके इस खर्च में कमी लायी जा सकती है।

भारत में इस समय केवल जीएम तकनीकी से विकसित कपास को ही उगाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जीएम बैंगन को व्यावसायिक उत्पादन के लिए जारी किया गया था लेकिन पर्यावरण कार्यकत्ताओं ने इसे खेती और फसलों के लिए नुकसानदायक बताते हुए रूकवा दिया था। हर बार की तरह इस बार भी जीन सर्वर्धित अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जीईएसी) की सिफारिश का विरोध शुरू हो गया है। देश के किसान संगठनों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने इसे आत्मघाती बताते हुए सरकार से सिफारिश वापस लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि जीईएसी ने जीएम सरसों की गुणवत्ता और इसका पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया है। हांलाकि भारतीय अनुसंधान परिषद और भारत सरकार ने प्रदर्शनों, अध्ययनों और सोच समझकर ही इतना बड़ा फैसला लिया होगा। यदि जीएम सरसों के परिणाम सकारात्मक हैं तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

दूसरी तरफ जीएम फसलों के प्रति खासकर खाद्य फसलों के प्रति जो आंशकाएं हैं इनमें कुछ सच्चाई है तो यह निर्णय घातक भी हो सकता है। सरसों एक ऐसी फसल है जोकि मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों के लिए अधिक सहयोगी रहती है। सरसों की खेती के साथ मधुमक्खी पालन भी व्यापक रूप से किया जाता है। सरसों की फसल में मधुमक्खी परागण का कार्य भी करती है। मधुमक्खी सरसों के फूलों से पॉलन एवं नेक्टर एकत्र कर शहद उत्पादन करती है। लेकिन जीएम सरसों की फसल से जो पॉलन एवं नेक्टर ग्रहण करेगी और उससे जो शहद पैदा होगा उसका पूरा संघटन भी बदल सकता है। क्या जीएम सरसों की फसल से पॉलन एवं नेक्टर मिलने की

हाइड्रोपोनिक उत्पाद मिटटी में उगाई उपज से बेहतर...?

आजकल बढ़ती जनसंख्या और खेती के लिए कम होती जमीन को देखते हुए हाइड्रोपोनिक खेती एक अच्छा विकल्प बन सकता है। देश में बड़ी तेजी के साथ इस खेती का चलन भी बढ़ रहा है। अगर हम इस खेती से उत्पन्न होने वाली उपज और मिटटी में होने वाली उपज की गुणवत्ता की तुलना करें तो एक आदर्श दुनिया में, हाइड्रोपोनिक उत्पाद पोषण मूल्य और गुणवत्ता के मामले में मिट्टी में उगाई गई उपज से थोड़ा बेहतर होगा। वैसे तार्किक रूप से हाइड्रोपोनिक उत्पाद बनाम मिट्टी में उगाई गई उपज की पोषण गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन निम्नलिखित दो कारणों से केवल अंतर दिखाई देते हैं। एक पोषक तत्वों की लीचिंग और दूसरा मिट्टी का प्रकार।

पोषक तत्वों की लीचिंग: भारत में मिट्टी आधारित षि का एक बड़ा हिस्सा बारिश पर निर्भर है या बोर-वेल के माध्यम से भूजल निकालने के द्वारा बाढ़ सिंचाई विधियों का उपयोग करता है। ऐसी सिंचाई पद्धतियों का एक अंतर्निहित दोष यह है कि उर्वरक की एक बड़ी मात्रा मिट्टी के माध्यम से रिसती है और भूजल या आस-पास के जल निकायों में मिल जाती है। प्राकृतिक जल संसाधनों का प्रदूषण उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के सबसे बड़े प्रतिबंधों में से एक है।

दूसरी ओर, हाइड्रोपोनिक्स में पोषण विज्ञान, पुनरावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोपोनिक्स में, पोषक तत्वों से भरपूर पानी को बार-बार पौधों की जड़ों के माध्यम से पुनः परिचालित किया जाता है। यह पुनरावर्तन प्रक्रिया दो तरह से मदद करती है; एक, यह पोषक तत्वों की न्यूनतम बर्बादी सुनिश्चित करता है। दूसरा, पौधों की जड़ों में उनके लिए हर समय पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। इस कारण से, हाइड्रोपोनिकली उगाए गए पौधे में मिट्टी में उगाए गए पौधों की तुलना में बेहतर पोषण प्रोफ़ाइल होनी चाहिए।

मिट्टी का प्रकार: किसान द्वारा जोड़े गए पोषक तत्व, मिट्टी में ही कई ट्रेस तत्व और पोषक तत्व हो सकते हैं, जिनमें से कुछ फायदेमंद हो सकते हैं और कुछ हानिकारक हो सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में, जब तक किसान बाहरी रूप से पोषक तत्व नहीं जोड़ता, तब तक पौधे को वह पोषक तत्व कभी नहीं मिल सकता है। इस कारण से, मिट्टी में उगाई जाने वाली उपज में हाइड्रोपोनिक रूप से उगाए गए समकक्षों की तुलना में कुछ तत्वों (खराब या अच्छा) की मात्रा अधिक हो सकती है।

फसल के बाद पौधे में पोषक तत्वों की हानि: जैसे ही एक पौधे को काटा जाता है, वह पोषक तत्वों को खोना शुरू कर देता है। तापमान जितना अधिक होगा, नुकसान उतना ही अधिक होगा। मिट्टी का भोजन ज्यादातर दूर-दराज के स्थानों में उगाया जाता है और आपूर्ति श्रृंखला से गुजरने में लंबा समय लगता है, जब तक आप इसका सेवन करेंगे तब तक इसमें बहुत कम पोषक तत्व बचे होंगे। हाइड्रोपोनिक्स में, अधिकांश फार्म बड़े शहरों के भीतर या उसके आस-पास स्थापित होते हैं और उपभोक्ता को अपनी उपज ताजा प्रदान करते हैं, जिससे मिट्टी की तुलना में अच्छा पोषक तत्व होता है।

पोषक तत्वों की कुशल आपूर्ति: एक हाइड्रोपोनिक प्रणाली में, पोषक तत्वों को सटीकता और सटीकता के साथ आपूर्ति की जाती है, जिससे न केवल प्रति पौधे उर्वरक आवश्यकताओं को कम किया जाता है, बल्कि पौधों को सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ने की इजाजत मिलती है। पौधों को पोषक तत्वों की तलाश में अपनी जड़ प्रणाली को विकसित करने में समय नहीं लगाना पड़ता है, जैसा कि वे पारंपरिक खेती में करते हैं। इसके अतिरिक्त, पोषक तत्वों से भरपूर पानी की संतुलित और अच्छी तरह से आपूर्ति के कारण, पौधों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और सभी किस्में समान रूप से विकसित होती हैं और सफलता की समान संभावना होती है।

कोई कीट, रोग या खरपतवार नहीं: बड़ी संख्या में रोग और कीट मिट्टी से पैदा होते हैं जो बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान आपके बगीचे को संक्रमित करते हैं। इसलिए, मिट्टी की खेती में, कीट और बीमारियाँ प्रमुख चुनौतियाँ हैं, जिनका किसानों को सामना करना पड़ता है। यह मानसिक रूप से बहुत हतोत्साहित करने वाला और आर्थिक रूप से एक बड़ा जोखिम हो सकता है। एक और भय वाली बात जो पारंपरिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके हो सकती है, वह है खरपतवार के बीज मिट्टी में निष्क्रिय रह सकते हैं और आपके बगीचे के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के आने पर फिर से उग सकते हैं। और कीट और रोग पौधों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं और बीज को कम उत्पादक बना सकते हैं। हाइड्रोपोनिकली (बिना मिट्टी के) उगाने से कीटों और बीमारियों से लड़ने का तनाव कम होगा।

तो अब हम समग्र रूप से जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक खेतों में, उगाए गए पौधे अत्यधिक नियंत्रित वातावरण में होते हैं जिसमें प्रकाश की तीव्रता, तापमान, आर्द्रता की बारीकी से निगरानी और नियंत्रण किया जाता है और बढ़ते समाधान को सख्ती से नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार, यह केवल हमारे स्वास्थ्य के बड़े लाभ में है कि एक ऐसे माध्यम में बढ़ने की सलाह दी जाती है जो हानिकारक तत्वों के उपयोग को कम करने या कम से कम करने में मदद करता है जो दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि मिट्टी में उगाई गई और हाइड्रोपोनिकली उगाई गई सब्जियों के बीच एक विकल्प दिया गया, हाइड्रोपोनिक इसका उत्तर है।

पर्यावरण की रक्षा में हर व्यक्ति दे अपने हिस्से का योगदान

पर्यावरण रक्षा के लिए सामूहिक प्रयास बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारों के स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कुछ किया जा रहा है वह तब तक एक सीमा तक ही प्रभावी रहेगा जब तक उन्हें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस के साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले कार्यक्रम मिशन लाइफ का शुभारंभ करते हुए लोगों से प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी समझने की जो अपील की, उसे न केवल सुना जाना चाहिए, बल्कि उस पर अमल भी किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए यह समझा जाना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन प्रकृति के अंधाधुंध दोहन का नतीजा है और उससे उपजी चुनौतियों से अब तभी निपटा जा सकता है, जब हर कोई पर्यावरण की रक्षा में अपने हिस्से का योगदान देने के लिए आगे आएगा। प्रगति करते समय प्रकृति और पर्यावरण के हितों का ध्यान रखना समय की ऐसी मांग है, जो हर हाल में पूरी होनी चाहिए। मिशन लाइफ सरीखे आयोजनों की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि आम लोग इससे तो परिचित हैं कि जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन के समक्ष किस तरह की गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन वे इससे अनजान ही अधिक हैं कि इन समस्याओं का सामना कैसे किया जा सकता है? मिशन लाइफ इस प्रश्न का उत्तर देता है। यह लोगों को बताता है कि वे अपनी जीवन शैली में कैसे परिवर्तन लाकर पर्यावरण की रक्षा में सहायक बन सकते हैं। शायद यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन केवल नीतिगत विषय नहीं है, बल्कि यह आम जनता से जुड़ा मसला है। वैसे तो हम भारतीय प्रकृति को संरक्षण देने के तौर-तरीकों से अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन आधुनिक जीवनशैली के चलते उनकी महत्ता को ओझल कर रहे हैं। यह सही समय है कि मिशन लाइफ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को इससे अवगत कराया जाए कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में किस तरह के बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह संदेश जन-जन तक जाना चाहिए कि लोग अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि सरकारों के स्तर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कुछ किया जा रहा है, वह तब तक एक सीमा तक ही प्रभावी रहेगा, जब तक उन्हें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। हम भारत के लोगों को मिशन लाइफ कार्यक्रम के जरिये विश्व समुदाय के समक्ष पर्यावरण रक्षा का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। असमय वर्षा, ग्लेशियरों का पिघलना, तूफानों का क्रम बढ़ना और कहीं आवश्यकता से अधिक बरसात तो कहीं अवर्षण आदि जलवायु परिवर्तन के ही दुष्परिणाम हैं। आयनोस्फीयर- ऊपरी वायुमंडल का आवेशित भाग भी सीओ 2 की मात्रा बढ़ने के कारण, बल्कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण भी इसके बदलने का अनुमान है। आयनोस्फीयर में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को समझना उन त्रुटियों को ठीक करने के लिए महत्वपूर्ण है जो वे जलवायु निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपग्रह-आधारित समुद्र स्तर माप की गणना करते हैं। इलेक्ट्रॉन गणना में सबसे बड़ा परिवर्तन दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और पश्चिमी अफ्रीका में हो सकता है। अध्ययन में सलाह दी गई है कि आगे के अध्ययन इन परिवर्तनों की निगरानी करें और उपग्रह-आधारित आंकड़ों के प्रयोगों पर प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए काम करें।

उत्पादन के लिए भूमि शोधन और बीजोपचार के बाद ही करें बोवनी

चना देश की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी, आमदनी वाली फसल

भोपाल। जागत गांव हमार

चना देश की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। चने को दालों का राजा भी कहा जाता है। इसका उत्पादन उत्तरी भारत मे बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। संरक्षित नमी वाले शुष्क क्षेत्रों में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। इसे रबी मौसम में उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए मध्यम वर्षा (60-90 सेमी वार्षिक) और सर्दी वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त हैं। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। चने की खेती हल्की से भारी मिट्टी में की जाती है। लेकिन अधिक जल धारण और उचित जल निकास वाली मिट्टी सर्वोत्तम रहती है, लेकिन लवणीय और क्षारीय भूमि जहां जल निकास की समस्या है वो भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है इसके अच्छे विकास के लिए 5.5 से 7 पीएच वाली मिट्टी अच्छी होती है।

बीजोपचार

- जड़गलन और उकटा की रोकथाम के लिए बोवनी पूर्व 10 किलो ट्राइकोडर्मा हरजेनियम या 1.5 ग्राम कार्बेन्डेजिम या 2.5 ग्राम कार्बेन्डेजिम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित करें।
- एजोटोबैक्टर और पीएसबी कल्चर पाउडर के तीन पैकेट /600 ग्राम कल्चर से एक हेक्टेयर क्षेत्र के बीज को उपचारित कर बोने पर नत्रजन एवं फॉस्फोरस की बचत की जा सकती है।
- बारानी और सिंचित क्षेत्रों में बोवनी से पहले 4 मिली क्लोरोपाइरिफॉस (20 ईसी) या 2 मिली इमिडाक्लोप्रीड (17.8 एसएल) मात्रा को 50 मिली पानी मे घोल बनाकर 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें।
- **बुवाई का समय-** सिंचित चने की बोवनी 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करें, लेकिन उपयुक्त समय 25 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक है।

चने की उन्नत किस्में

चने की देशी किस्में

- जीएनजी 2171 (मीरा)- सिचिंत क्षेत्रो में समय पर बोवनी के लिए उपयुक्त किस्म है। दाना कत्थई रंग का होता है, इसकी फली में 2 या 2 से अधिक दाने पाए जाते हैं। ये किस्म लगभग 150 दिन में पक जाती है। इसकी औसत उपज 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है।
- जीएनजी 1958 (मरुधर)-यह किस्म झुलसा और जड़गलन रोग के प्रति सहनशीलता रखती है। बीज का रंग हल्का भूरा होता है। यह औसत 145 दिन में पक जाती है। इसकी औसत उपज 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है।
- जीएनजी 1581 (गणगौर)-यह किस्म झुलसा, जड़गलन, एस्कोकाईटा ब्लाइट आदि रोगों के प्रति औसत प्रतिरोधकता रखती है बीज का रंग हल्का पीले रंग का होता है, इसकी औसत उपज 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है।
- आरवीजी 202-इस किस्म के पौधे की ऊंचाई दो फीट से भी कम रहती है, जिससे इस पाले का असर कम पड़ता है। इसमें प्रति हेक्टेयर 22 से 25 क्विंटल तक पैदावार मिलती है।

देशी चने की देरी से बोई जाने वाली किस्म

1. जीएनजी 2144 (तीज)-इस किस्म की बोवनी दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक कि जा सकती है। बीज मध्यम आकार के हल्के भूरे रंग का होता है। यह 130-135 दिन में पककर तैयार हो जाती है इसकी औसत उपज 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आंकी गई है।
2. जीएनजी 1488 (संगम)-यह किस्म झुलसा, शुष्क जड़गलन, एस्कोकाईटा ब्लाईट, फली छेदक आदि के प्रति औसत प्रतिरोधकता पाई गई है। बीज भूरे रंग होते है, जिनकी सतह चिकनी होती है। यह 130 से 135 दिन में पक जाती है और उत्पादन 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल जाता है।

काबुली चने की किस्म

- जीएनजी 1969-इसके दाने का रंग मटमेला सफेद क्रीम रंग का होता है। झुलसा और जड़गलन आदि रोगों के प्रति मध्यम सहनशीलता रखती है। इसकी औसत पकाव अवधि 146 दिन है इसकी औसत पैदावार 22 क्विंटल तक पाई जाती है।
- जीएनजी 1499 (गौरी)- इसके बीज का रंग मटमेला सफेद होता है 143 दिन में पककर तैयार हो जाती है। औसत पैदावार 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाती है।
- जीएनजी 1292-147 दिन में पक जाती है झुलसा, एस्कोकाईटा ब्लाइट, शुष्क आदि रोगों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी है। औसत उत्पादन 23-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हो जाता है।
- भूमि उपचार-किसानों के चने में कई प्रकार के रोग और कीट लगते हैं। उनके नियंत्रण के लिए भूमि उपचार जरूरी है।
- दीमक व कटवर्म से बचाव के लिए क्युनालफॉस चूर्ण 6 किलो प्रति बीघा आखिरी जुताई से पहले मिलाएं।
- दीमक नियंत्रण के लिए बिजाई से पूर्व प्रभावित क्षेत्र में 400 मिली क्लोरो पाइरिफॉस या 200 मिली इमिडाक्लोप्रीड की 5 लीटर पानी का घोल बनाकर 100 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करें।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा

नारियल की खेती को बढ़ावा देगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

देश के कई राज्यों में बड़ पैमाने पर नारियल की खेती होती है। एक बड़ी आबादी नारियल की खेती और इससे जुड़े उद्योग से जुड़ी हुई है। देश में नारियल आधारित उद्योगों की संख्या में वृद्धि के साथ ही बाजार में नए उत्पाद और रोजगार के कई अवसर भी बढ़ रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोयम्बटूर में नारियल समुदाय के किसानों के सम्मेलन में कहा है कि केंद्र सरकार, देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देने के लिए नारियल समुदाय से जुड़े किसानों को हरसंभव सहायता प्रदान करती रहेगी। पिछले कुछ वर्षों में अनुसंधान-विकास के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए हैं, उनके फलस्वरूप खेती व प्रसंस्करण क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं और उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को और अधिक उन्नत बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए इसे मजबूत बनाना, आगे बढ़ाना व किसानों के लिए मुनाफे की खेती सुनिश्चित करना केंद्र एवं राज्य सरकार का दायित्व है।

नारियल की खेती में भारत अग्रणी

कृषि अर्थव्यवस्था में नारियल की खेती का योगदान काफी अहम है। नारियल की खेती में भारत अग्रणी है व दुनिया के तीसरे बड़े उत्पादकों में से एक हैं। देश में नारियल के अधीन क्षेत्र का 21 प्रतिशत, उत्पादन का 26 प्रतिशत तमिलनाडु का योगदान है। नारियल प्रसंस्करण गतिविधियों में तमिलनाडु पहले नंबर पर है व नारियल खेतीगत क्षेत्र की दृष्टि से कोयम्बटूर प्रथम है, जहां 88,467 हेक्टेयर क्षेत्र में नारियल की खेती हो रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां के लोग नारियल क्षेत्र के विकास व कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

19 नारियल उत्पादक कंपनियां

नारियल विकास बोर्ड छोटे-सीमांत किसान एकीकृत कर त्रिस्तरीय किसान समूह बना रहा है। राज्य में वर्तमान में 697 नारियल उत्पादक समितियां, 73 नारियल उत्पादक फेडरेशन एवं 19 नारियल उत्पादक कंपनियां हैं। भारत में प्रति वर्ष 3,638 मिलियन नारियल की प्रसंस्करण क्षमता के साथ 537 नई प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए समर्थन दिया गया है। यह सफलता बोर्ड द्वारा देश में कार्यान्वित मिशन कार्यक्रम के जरिए हासिल हुई है। इनमें से 136 इकाइयां तमिलनाडु की हैं, जो रोजगार के अवसर सृजित कर रही हैं। किसानों की माली हालत सुधारने में भी मदद कर रही हैं।

कृषि मंत्री पटेल और प्रभारी मंत्री सिलावट का आह्वान, बारंगा में किसानों को प्राकृतिक खेती का दिलाया संकल्प

सभी किसान मिल कर हरदा को बनाएं नम्बर वन जिला

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि सभी मिल-जुल कर प्रयास करें और हरदा को नम्बर वन जिला बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जिले के प्रभारी और जल-संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि हरदा के विकास कार्य प्राथमिकता से कराए जाना सुनिश्चित करें। मंत्रीद्वय हरदा जिला पंचायत सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मंत्रीद्वय ने सतना में आयोजित राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना गृह-प्रवेश कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर हरदा जिले के 495 हितग्राही को आवासों की सौगात दी। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि हरदा गेहूं, चना और मूंग उत्पादन में अग्रणी जिला है। किसान खेतों की मेड़ पर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए गए अंकुर अभियान में पौध-रोपण करें। हरदा जिले को प्राकृतिक खेती में भी अव्वल बनाना है। उन्होंने किसानों की आय को दोगुना करने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सभी को सतत सम्मिलित प्रयास करने के निर्देश दिए।

रासायनिक खेती धीरे-धीरे कम करें

कृषि विकास मंत्री ने कहा है कि हरदा जिले के किसान समन्वित प्रयास कर जिले को प्राकृतिक खेती में नंबर वन बनाए। उन्होंने गृह ग्राम बारंगा में किसानों को प्राकृतिक खेती करने का संकल्प दिलाया। कृषि मंत्री ने कहा है कि किसान प्राकृतिक खेती करें। रासायनिक खेती धीरे-धीरे कम करें। उन्होंने सभी नागरिकों से बिजली, पानी बचाने तथा गौ-माता के संरक्षण के लिए प्रयास करने और अपने खेत की मेड़ों पर पौध-रोपण करने की अपील की। कृषि मंत्री ने कहा कि वे स्वयं अब 10 एकड़ में प्राकृतिक खेती करेंगे। अगले वर्षों में अपनी खेती शत-प्रतिशत प्राकृतिक पद्धति से ही करेंगे।

किसान पराली न जलाएं

मंत्री पटेल ने अपील की कि फसल कटने के बाद पराली न जलाएं। किसान अपनी फसल की ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग कराएगें तो उनकी आय बढ़ेगी। मंत्री ने कलेक्टर ऋषि गर्ग से कहा कि जिले में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाए, जिससे अन्य किसान भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित हो। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि प्रति हेक्टेयर गेहूं, चना और मूंग उत्पादन में हरदा नम्बर वन जिला बना है। अब प्राकृतिक खेती के मामले में भी हरदा जिला नम्बर वन हो।

1229 विलेज में सफाई अभियान शुरू

कृषि वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देने 639 गांवों को लिया गोद

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार द्वार 'स्वच्छता और सरकार में लंबित मामलों को कम करने' पर ध्यान देने के लिए दो अक्टूबर से विशेष अभियान 2.0 चलाया जा रहा है, जो 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। यह अभियान सरकारी कार्यालयों में मामलों और स्वच्छता के सही समय पर निपटान के महत्व को सुदृढ़ करता है। इस अभियान के दौरान कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग व इससे संबद्ध और स्वायत्त निकायों के क्षेत्र/बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष अभियान 2.0 में आईसीएआर के सभी 113 संस्थान और 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) हिस्सा ले रहे हैं। यह विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इस अभियान के तहत लंबित सांसद/वीआईपी मामलों व लोक शिकायतों के निपटान और हार्डकॉपी फाइलों/अभिलेखों की छंटाई के अलावा विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन कर रहे हैं। इन गतिविधियों में वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग कर माइक्रोबियल आधारित कृषि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गांवों को गोद लेना, स्वच्छता के बारे में जागरूकता कार्यक्रम, फसल अवशेष प्रबंधन, अपशिष्ट व संपत्ति पर तकनीकों का प्रदर्शन, किसानों के साथ गांवों की सफाई कार्यक्रम, विभिन्न विषयों जैसे सफाई व स्वच्छता आदि पर विद्यालय के बच्चों को जागरूक करना शामिल हैं।

6,000 लाभार्थियों की भागीदारी - अभियान के दौरान केवीके के उपरोक्त उल्लेखित विषयवस्तुगत क्षेत्रों में कुल 7,215 गतिविधियां आयोजित की गईं, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों (केवीके कर्मचारी, किसान, नागरिक समाज के सदस्य, विद्यालय के बच्चे और अन्य गणमान्य व्यक्ति) की भागीदारी शामिल है। केवीके परिसरों, गांवों, विद्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित स्वच्छता पर लगभग 2,170 जागरूकता कार्यक्रमों में लगभग 46,000 लाभार्थियों की अधिकतम भागीदारी दर्ज की गई।

1,229 गांवों में सफाई का काम शुरू किया

केवीके ने फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित कुल 519 गतिविधियों का संचालन किया। इनमें लगभग 21,437 प्रतिभागियों की भागीदारी के साथ वर्मी कंपोस्टिंग तकनीक का उपयोग करके कृषि अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए कुल 639 गांवों को गोद लिया गया। वहीं, 20,000 प्रतिभागियों ने विद्यालय के बच्चों, किसानों और समाज के अन्य सदस्यों की भागीदारी के साथ 1,229 गांवों में सफाई का काम शुरू किया। 585 गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय के 14,700 बच्चों को सफाई व स्वच्छता जैसे विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया। केवीके कर्मचारियों के 5,496 सदस्य कार्यालय व परिसरों की सफाई और 1,130 विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कचरे के निपटान में शामिल थे।

-बाजार कीमत से 8 रुपए कम में राज्यों को चने देने का फैसला

देश में दालों का बफर स्टॉक हुआ 43 लाख टन

भोपाल। जागत गांव हमार

धान-गेहूं के बाद अब देश में सभी तरह की दालों का भी बफर स्टॉक हो गया है। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार के मुताबिक, देश में 43 लाख टन सभी तरह की दालों का बफर स्टॉक है। फिलहाल, दालों का यह स्टॉक पूरे देश के लिए पर्याप्त है। ऐसे में चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे भी हर साल त्योहारी सीजन में खाने- पीने की चीजों की कीमतें थोड़ी बढ़ जाती हैं। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप इन दिनों में बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी सरकार के पास जरूरत से ज्यादा खाद्य भंडारण है। रोहित कुमार ने कहा कि सरकार के पास इस साल (2022-23) के लिए 251056 द्रह्ल प्याज का भंडार है। जबकि, सभी दालों का बफर स्टॉक 43 लाख टन है। उन्होंने कहा कि देश के अलग- अलग राज्यों में अलग- अलग दालों की मांग ज्यादा होती है। इसलिए पर्याप्त मात्रा के बावजूद इम्पोर्ट भी कराया जा रहा है। वहीं, मिड डे मील या अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने बाजार कीमत से 8 रुपये कम में राज्यों को चने देने का फैसला लिया है। लगभग 88 हजार टन चना इस योजना के तहत राज्यों को दिया गया है।

सरकारी गोदामों में 227 लाख टन गेहूं

बीते दिनों केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा था कि बाजार में महंगाई बेकाबू नहीं है। सरकार के पास गेहूं प्रयाप्त मात्रा में है। सरकार पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए बाजार में अतिरिक्त अनाज उतारेगी। सुधांशु पांडेय ने एफसीआई के पास उपलब्ध स्टॉक की डिटेल्स देते हुए कहा कि सरकार के पास सरकारी गोदामों में 205 लाख टन के आवश्यक बफर स्केल के मुकाबले 227 लाख टन गेहूं उपलब्ध है।

खेत को जलभराव से बचाएं, फल में मिलेगी अच्छी पैदावार

लीची की खेती किसानों को कर देगी मालामाल

भोपाल। जागत गांव हमार

लीची की खेती के लिए सामान्य पीएच मान वाली गहरी बुलई दोमट मिट्टी अत्यंत उपयुक्त होती है। अधिक जल सोखने वाली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी में लीची की खेती करने से पौधों की अच्छी प्रगति और बढ़िया फलोत्पादन होता है। खेत में जलभराव लीची के उत्पादन पर प्रतिकूल असर डालता है। किसान लीची की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली कियारी बनाएं। इससे किसानों को फल में अच्छी पैदावार मिलेगी।

लीची के लिए जमीन की तैयारी: गुलाबरी, स्वर्ण रूपा, शाही और देहरादून, कलकत्तिया और चाइना लीची की उन्नत किस्में मानी जाती हैं। किसान लीची के बीज रोपने से पहले अपने खेत की दो से तीन बार तिरछी जोताई करें और फिर खेत पर पाटा लगाकर इसे समतल करें। अब खेत में इस तरह कियारियां बनाएं कि इसमें सिंचाई के समय पानी जमा न हो। लीची के बिजाई के लिए

कम से कम दो वर्ष पुराने पौधे चुनें। क्यारियों का फासला 8-10 मीटर का फासला रखें। लीची का बीजाई सीधे बीज लगाकर और पनीरी लगाकर की जाती है।

गूटी विधि सबसे अच्छी

गूटी तैयार करने के लिए लीची के एक 5-7 साल पुराने वृक्ष से स्वस्थ और सीधी डाली चुन लें। अब डाली के शीर्ष से 40-45 सेंटीमीटर नीचे किसी गांठ के पास गोलाई में 2.5-3 सेंटीमीटर का चौड़ा छल्ला बना लेते हैं। छल्ले के ऊपरी सिरे पर आईबीए के 2000 पीपीएम पेस्ट या रूटेक्स का लेप लगाकर छल्ले को नम मॉस घास से ढककर ऊपर से पारदर्शी पॉलीथीन का टुकड़ा लपेट कर सुतली से कसकर बांध दें। गूटी बांधने के लगभग 2 माह के अंदर जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। इस समय डाली की लगभग आधी पत्तियों को निकालकर एवं मुख्य पौधे से काटकर नर्सरी में आंशिक छायादार स्थान पर लगा दिया जाता है।

खाद और सिंचाई

लीची के छोटे पौधों की प्रगति के समय एक हफ्ते के अंतराल से नियमित सिंचाई करें। बीज रोपाई के बाद फसल में 5-10 किग्रा गली, सड़ी रूड़ी खाद के साथ यूरिया 25-50 ग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 50-100 ग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 10-30 ग्राम प्रति पौध अंकुरण के लिए लगाएं। पौधों को शुरुआती दौर में अच्छा आकार देने के लिए कटाई-छंटाई करना आवश्यक है।

नर्मदा का जल किसानों के खेतों तक पहुंचाया जाएगा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नर्मदा से पाइप लाइन बिछा कर किसानों के खेतों तक सिंचाई के लिये पानी पहुंचाने के प्रबंध किए जाएंगे। इसके लिये 102 करोड़ रुपए की लागत की सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है। ऐसे किसान, जिनकी ढाई-ढाई हेक्टयर भूमि है, उन्हें इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। विशेष कर उन किसानों को जिन्हें वारना नहर से पानी नहीं मिल पा रहा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सीहोर जिले के बुधनी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत गादर में मुख्यमंत्री जन-सेवा शिविर को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिविर में आए ग्रामीणों को केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें लाभान्वित करने जन-सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणजन सजग होकर योजनाओं का लाभ लें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति शासन की योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिये डोर-टू-डोर सर्वे भी किया जाए। मुख्यमंत्री को शिविर में मूक बधिर रंजीत चौहान ने अपनी समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने हितग्राही को यथाशीघ्र लाभ दिलाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शिविर में आए आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन के साथ शिविर का शुभारंभ किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं में हितलाभ और स्वीकृति-पत्र वितरित किए। विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव ने भी संबोधित किया। शिविर में जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

गाय को गौ-ग्रास अर्पित करने का आह्वान

गोपाष्टमी पर गौ-शालाओं में होंगे गौ-पूजन कार्यक्रम

भोपाल। मध्यप्रदेश गौ-संवर्द्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने प्रदेश की सभी गौ-शाला संचालकों को आगामी गोपाष्टमी-एक नवम्बर को गौ-शालाओं में गौ-पूजन कार्यक्रम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में गौ-भक्तों और पशु प्रेमियों को आमंत्रित कर गौ-पूजन में सम्मिलित करें। पूजन के बाद गाय के महत्व पर केन्द्रित संगोष्ठियाँ की जाये। संगोष्ठियों में अनुभवी गौ-सेवकों, गौ-पालकों और विद्वज्जनों को आमंत्रित करें। महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरि ने प्रदेश के गौ-पालकों, गौ-भक्तों और गौ-प्रेमियों से अपील की है कि गोपाष्टमी पर अधिक से अधिक संख्या में अपनी निकटतम गौ-शाला पहुंच कर गौ-पूजन में शामिल हों। गायों और बछड़े-बछियों को गौ-ग्रास अर्पित करें। उन्होंने गौ-भक्तों से आग्रह किया कि यदि उनके घर में नन्हें बालक-बालिकाएँ हैं, तो उनको भी अपने साथ गौ-शाला ले जाएँ और उनमें गौ-संरक्षण के संस्कार रोपित करें। गायों को हरी घास, गुड़-रोटी, भीगी चने की दाल आदि खिलाएं। गौ-ग्रास के निमित्त दान राशि भी गौ-शालाओं में दें।

प्रदेश में आयुष औषधियों के उत्पादन को किया जा रहा प्रोत्साहित

-राज्य मंत्री ने जयपुर में आयुर्वेद फार्मेसी लेब का किया निरीक्षण

भोपाल। आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर कावरे ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयुर्वेद फार्मेसी लेब का निरीक्षण किया। उन्होंने लेब में बनाई जा रही 100 से अधिक आयुर्वेदिक दवाइयों के उत्पादन की प्रक्रिया को देखा। मंत्री कावरे ने बताया कि मध्यप्रदेश औषधीय पौधों के मामले में काफी समृद्ध है। प्रदेश में आयुष दवाइयों के उत्पादन की बड़ी संभावनाएं हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये देवारण्य योजना शुरू की है। राज्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश का 31 प्रतिशत भू-भाग वन से आच्छादित है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आयुष औषधियों के उत्पादन में निवेश करने वाली फार्मेसी कंपनी को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। आयुष राज्य मंत्री कावरे को फार्मेसी कंपनी के संचालकों द्वारा उत्पादित दवाइयों के मार्केटिंग के संबंध में भी जानकारी दी गई।

-होगा अच्छा उत्पादन, जानिए उन्नत किस्में

वैज्ञानिक तरीके से करें चने की खेती

भोपाल। जागत गांव हमार

चने की खेती पूरे भारत में होती है। अगर किसान चने की खेती वैज्ञानिक तरीके से करें तो वे अच्छी कमाई कर सकते हैं। ऐसे भी अभी चने की बुवाई करने का समय चल रहा है। दरअसल, चना एक शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। रबी मौसम में इसकी खेती की जाती है। अक्टूबर और नवंबर का महीना इसकी बोवनी के लिए अच्छा माना गया है। इसकी खेती के लिए सर्दी वाले क्षेत्र को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसकी खेती के लिए 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त है। खास बात यह है कि चने की खेती हल्की से भारी मिट्टी में भी की जा सकती है। लेकिन चने के अच्छे विकास के लिए 5.5 से 7 पीएच वाली मिट्टी अच्छी मानी गई है। इसलिए चने की बुआई करने से पहले मिट्टी का शोधन जरूरी है।

मिट्टी का शोधन जरूरी - किसी भी फसल की खेती करने से पहले मिट्टी को शोधन जरूरी माना गया है। इसलिए यह नियम चने की खेती पर भी लागू होता है। क्योंकि चने की फसल में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। ऐसे में चने की बोवनी

करने से पहले मिट्टी शोधन जरूरी है। किसानों को खेती की आखिरी जुताई करने से पहले दीमक व कटवर्म से बचाव के लिए मिट्टी में क्युनालफॉस (1 l5 प्रतिशत) चूर्ण 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से मिला देना चाहिए। फिर, दीमक नियंत्रण के लिए बिजाई से पहले 400 मिली क्लोरोपाइरिफॉस (20 ईसी) या 200 मिली इमिडाक्लोप्रीड (17.8 एसएल) की 5 लीटर पानी का घोल बनाकर तैयार कर लें। फिर, 100 किलो बीज को उस घोल में अच्छी तरह से मिला दें। ऐसा करने से फसल अच्छी होती है। इसी तरह जड़ गलन और उखटाकी समस्या से बचने के लिए बुवाई से ट्राइकोडर्मा हरजेनियम और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस जैव उर्वरक का उपयोग करें।

चने की उन्नत किस्में

बीजीडी 72- बीजीडी 72 के दानों का आकार बड़ा होत है। यह विल्ट, एस्कोकाइटा ब्लाइट, और जड़ सड़न से प्रतिरोधक है। केऐके 2- चने का यह किस्म बड़ा काबुली चना है। यह जल्दी पकन वाली किस्म है। इसकी पत्तियां हल्क हर रंग की होती हैं। यह सिंचित और वर्षाधारित चने की किस्म है। जेजी-7- जेजी-7 सवहनी विल्ट से प्रतिरोधक है। अच्छी शाखाएं वाली किस्म हैं। इसके बीज मध्यम बड़े आकार के होत हैं। सिंचित और असिंचित क्षेत्रों दोनों के लिए यह उपयुक्त है। जेजी 130- आकार में बड़ा है। इसके 100 बीजों का वजन 25 ग्राम होता है। पौध में अच्छी शाखाएं और पत्तियां हल्की हरी होती हैं। दानें चिकन और पील भूरे से रंग के होत हैं। यह फयूजेरियम विल्ट, जड़ सड़न से प्रतिरोधक है। हेलीकॉवरपा से भी सहनशील है।

सोलर प्लांट की नई इकाई स्थापित करने प्रस्ताव तैयार

मऊगंज में 458 हेक्टेयर में बनेगा 250 मेगावॉट का सोलर प्लांट

» रीवा बनेगा ऊर्जा हब, बिजली की किल्लत होगी दूर

» ऊर्जा विभाग ने प्रशासन से मांगी 458 हेक्टेयर भूमि

भोपाल। जागत गांव हमार

रीवा उर्जा हब बनने की कगार पर है। मऊगंज में सोलर प्लांट की नई इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है। बदवार पहाड़ पर 750 मेगावॉट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट सफलता पूर्वक स्थापित करने के बाद बीते कई वर्षों से जिले में नए स्थान की तलाश की जा रही थी।

कई स्थानों पर तकनीकी पेंच की वजह से प्लांट स्थापित करने में रुकावट आई पर अब एक बार फिर मऊगंज क्षेत्र में नए प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके लिए तकनीकी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग ने एक बार फिर से प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें प्रशासन से 558 हेक्टेयर भूमि की मांग की गई है। यदि यह भूमि उपलब्ध हो जाती है तो रीवा जिले में 250 मेगावॉट क्षमता का एक और सोलर पॉवर प्लांट प्रारंभ हो जाएगा। इस दिशा में कार्य तेजी से चल रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जिला प्रशासन से कहा है कि जल्द ही भूमि की व्यवस्था कर प्रस्ताव तैयार कराएं। इसका कार्य जल्द पूरा कराने के लिए वह मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे। आने वाले समय में रीवा जिले को ऊर्जा उत्पादन का हब बनाने की तैयारी है।

अभी यहां हाइडल पावर प्लांट की सिरमौर में 315 मेगावॉट की इकाई है। वहीं कई जगह छोटे प्लांट लगाने की योजना चल रही है। सोलर पॉवर प्लांट का गुढ़ तहसील के बदवार पहाड़ में 750 मेगावॉट का प्लांट है। अब जिले में कचरे से भी बिजली उत्पादन की तैयारी है इसके लिए रायपुर कर्चुलियान के पास पहड़िया में छह मेगावॉट का पॉवर प्लांट लगाया जा रहा है। सरकार ने भी कहा है कि यहां सोलर प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित है, इस कारण दूसरे स्थानों पर भी नए

पहले राजस्व की भूमि पर ही लगेगा प्लांट

मऊगंज अनुभाग में नए सिरे से सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए 558 हेक्टेयर भूमि की जरूरत बताई गई है। इसमें पूरी भूमि राजस्व विभाग की है। तकनीकी रूप से कोई अड़चन नहीं आए इस कारण अभी राजस्व की भूमि को ही चुना गया है। इसके बाद योजना का विस्तार होगा। कुछ समय पहले ही सीतापुर। मऊगंज क्षेत्र में एक हजार हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर नए सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस क्षेत्र में वनभूमि का भी बड़ा हिस्सा फंस रहा था, इस कारण वन विभाग से एनओसी मांगी गई थी, लेकिन विभाग ने वनभूमि देने से इंकार कर दिया था। अब वन भूमि के हिस्से को पहले चरण में अलग रखा गया है। यहां पर प्लांट स्थापित किया जाएगा। बाद में जब उसका विस्तार होगा तो वन विभाग से फिर भूमि मांगी जाएगी।

90 फीसदी सब्सिडी के साथ किसानों को सोलर प्लांट लगाने की सुविधा

इधर, महंगी बिजली और बिजली कटौती की समस्या से किसानों को मिल सकती है निजात। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 90 प्रतिशत सब्सिडी पर सोलर पंप लगवा रही है। सोलर पंप लगाने के बाद किसानों को न तो बिजली का इंतजार करना पडेगा और न ही बिल देने के झंझट रहेगी। यही नहीं किसान अपने काम के बाद बची हुई बिजली बेचकर मुनाफा भी कमा सकता है। किसानों के लिए सिंचाई अभी भी गंभीर समस्या बनी हुई है। डीजल की कीमतें ज्यादा होने के चलते पंप सेट से फसलों की सिंचाई करना महंगा साबित हो रहा है। बिजली से भी सिंचाई की प्रकिया पूरा करना इतना सस्ता नहीं रह गया है। इस बीच सोलर पंप किसानों के लिए एक बढ़िया विकल्प उभर कर सामने आया है।

30 प्रतिशत लोन बैंक से

प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान पंचायतों और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों 30-30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही हैं। वहीं 30 प्रतिशत लोन बैंक के माध्यम से दिए जा रहे हैं।

15 लाख तक का बिजली उत्पादन

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर काम कर रही हैं। इसी कड़ी में पीएम कुसुम योजना भी लॉन्च की गई थी। किसान इस योजना का उपयोग करके खेतों मे सिंचाई की जरूरत को तो पूरा कर ही सकते हैं। इसके अलावा बढ़िया मुनाफा भी कमा सकते हैं। वह अपने स्थापित सोलर संयंत्र से 15 लाख रुपए तक का बिजली उत्पादन कर सकते हैं।

मटर की खेती में अच्छे उत्पादन के लिए खेती की विधि और उन्नत किस्में

भोपाल। देश में लगभग 7.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर मटर की बुवाई की जाती है। देश में इसका वार्षिक उत्पादन 8.3 लाख टन और उत्पादकता 1021 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश की यह प्रमुख फसल मानी जाती है। वैज्ञानिक के अनुसार बोनविले, अर्ली दिसंबर, जवाहर मटर, काशी उदय, पूसा प्रगति, अर्ली बैजर और काशी शक्ति को मटर उत्पादन के लिए बेहतरीन किस्में है।

मटर की खेती की उन्नत विधि

खेत की तैयारी| मटर की खेती के लिए गंगा के मैदानी भागों की गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती ह। हालांकि मटर की खेती बलुई, चिकनी मिट्टी में भी आसानी से की जा सकती है। खरीफ की कटाई के बाद खेत को दो से तीन बार हल से अच्छी तरह जोताई कर दें। अब इस पर पाटा लगा दें। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए मिट्टी में नमी होना जरूरी है।

बीज बोवनी का तरीका| बीज की बोवनी अक्टूबर-नवंबर के महीने में की जाती है। मटर की फसल के लिए प्रति एकड़ 35-40 किलोग्राम बीज का प्रयोग करें। बिजाई से पहले बीजों को कप्तान या थीरम 3 ग्राम कार्बेनडाजिम 2.5 ग्राम से प्रति किलो बीज का उपचार करें। रासायनिक तरीके से उपचार के बाद बीजों से अच्छी पैदावार के लिए उन्हें एक बार राइजोबियम लेगूमीनोसोरम से उपचार करें। इसमें 10 प्रतिशत चीनी या गुड़ का घोल होता है। इस घोल को बीजों पर लगाएं और फिर बीजों को छांव में सुखाएं। अब तैयार खेत में बीज को मिट्टी में कम से कम 2-3 सेंटीमीटर गहरा बोएं। इस विधि से बीजारोपड़ करने से 10-15 प्रतिशत फसल पैदावार में वृद्धि होगी।

खरपतवार पर नियंत्रण| मटर के बीज की किस्म के आधार पर एक या गोड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली गोड़ाई बीजारोपड़ के 2-3 हफ्ते बाद की जा सकती है। मटर की खेती में नदीनों की रोकथाम के लिए पैंडीमैथालीन 1 लीटर या बसालिन 1 लीटर प्रति एकड़ में डालें। बीजाई के 3-4 के दौरान इसका प्रयोग कर सकते हैं।

सिंचाई की विधि| यदि आप मटर की फसल धान की कटाई के बाद कर रहे हैं तो मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, ऐसे में बिना सिंचाई के भी आप मटर के बीजों की बुवाई कर सकते हैं। हालांकि अन्य खरीफ फसलों की कटाई के बाद बीज बोने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि क्या आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी है। पहली सिंचाई फूल निकलने से पहले और दूसरी फलियां भरने से पहले कर सकते हैं।

पौधे पर कीट प्रबंधन| मटर के पौधे के तने, पत्तियों, फूलों और फलियों को सुरंगी कीट, चेपा, कुंगी और सुंडी से खतरा होता है। ये फसल की वृद्धि रोक सकते हैं। इनके उपचार के लिए कार्बरिल 900 ग्राम को प्रति 100 लीटर पानी में डालकर प्रति एकड़ पर स्प्रे करें। जरूर पड़ने पर प्रति 15 दिन बाद इस घोल का स्प्रे कर सकते हैं।

-भोपाल हाट परिसर में 'उमंग 2022' मेला का आयोजन

नाबार्ड के उमंग ने 26 राज्यों के कृषि उत्पादों को दिया मंच

भोपाल। जागत गांव हमार

मप्र के लिए गौरव की बात रहेगी प्रदेश की राजधानी में देश के 26 राज्यों से आए स्वयं सहायता समूह, शिल्पकारों तथा कृषि उत्पाद संगठनों को एक मंच पर अपने उत्पाद प्रदर्शित एवं विक्रय करने का अवसर नाबार्ड के सहयोग से मिला। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के 'उमंग 2022' मेला भोपाल हाट परिसर में गत दिनों आयोजित किया गया। इस 9 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह बिक्री मेले का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल मंगु भाई पटेल ने किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में नाबार्ड की पिछले 40 वर्षों मप्र में कृषि एवं ग्रामीण विकास में की जा रही गतिविधियों की सराहना करते हुए ऐसे आयोजन इस क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं के लिए सर्वोत्तम बताया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड निरुपम मेहरोत्रा, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक नीरज निगम, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक विनोद कुमार मिश्रा, महाप्रबंधक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तरसेम सिंह जीरा, नाबार्ड के महाप्रबंधक एस. के. तालुकदार, पंकज यादव, उप महाप्रबंधक नाबार्ड कमर जावेद, नाबार्ड अधिकारी महेश रायचंदानी सहित नाबार्ड एवं अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी सह बिक्री मेले में स्टाल विभिन्न उत्पाद-संगठनों समूहों ने लगाए थे, इनमें प्राकृतिक जैविक तरीके से उत्पादित अनाज, व्यंजन, धातु से बनी मूर्ति, वस्त्र, चमड़े के उत्पाद, लकड़ी के खिलौने, अचार, बड़ी, पापड़ आदि की जमकर बिक्री हुई।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **अरविंद मिश्र, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)